

पाकिस्तान में यूएस-ईरान वार्ता को लेकर लग रही तमाम तरह की अटकलें

कुमार ने राज्य विधान परिषद के सदस्य पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 30 मार्च को पद छोड़ दिया था। जेडीयू प्रमुख 16 मार्च को उच्च सदन के लिए चुने गए थे और उन्हें चुनाव के बाद निर्धारित 14 दिनों के भीतर एमएलसी पद से इस्तीफा देना आवश्यक था। कुमार बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और हवाई अड्डे पर जद(यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित अन्य के नेताओं ने उनका स्वागत किया।

को संभलने या खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला। हादसे के बाद चारों ओर चीख-पुकार मच गई, क्योंकि निंद में गिरे लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। स्थानीय खुद तुर्त मदद के लिए दौड़े और कई लोगों को पानी से बाहर लेने की कोशिश की। जिला टट सीपी सिंह के अनुसार, हादसे में अब तक नौ लोगों की पुष्टि हो चुकी है, कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और यदि उसे समय पर सही बिल प्राप्त हो, तो वह भुगतान करने में विलम्ब नहीं हियचता है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के कार्या की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 'ओवरबिलिंग' की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, तो उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए।

उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। ममता बनर्जी लगातार भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, जबकि भाजपा राज्य में परिवर्तन और विकास का नारा बुलंद कर रही है। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। एक तरफ भाजपा अपने वादों और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपनी गढ़ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सम्पादकीय

दूसरी ओर स्कूल-कालेजों में शिक्षकों की वह भूमिका नहीं रही, जो सरस्ती से किशोरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। आज उनकी सोच को मोबाइल व सोशल मीडिया पर प्रसारित विकृत सूचनाएं प्रभावित कर रही हैं। समाज के व्यवहार में एक किस्म की आक्रामकता नजर आती है। वहीं दूसरी ओर आपराधिक गिरोह व गैंग भी अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने कि लिए किशोरों का इस्तेमाल ...

आक्रामकता पर अंकुश लगाने की पहल हो

होने के चलते उनकी वयस्क होने की उम्र घटाने की मांग होती है। इसकी वजह यह है कि किशोर गंभीर अपराधों में संलिप्तता के बावजूद किशोर अपराध से जुड़े कानूनों के लचीलेपन के चलते जेल से जल्दी रिहा हो जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद फिर दूसरे गंभीर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। यह गंभीर मुद्दा है जिसके समाधान को केंद्र सरकार को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए। दरअसल, इंटरनेट के तेजी से प्रसार और सोशल मीडिया में अपराधों से जुड़ी घातक सामग्री की उपलब्धता किशोरों में भटकाव को बढ़ावा दे रही है। हिंसक फिल्मों और अन्य माध्यमों में अपराध के तौर-तरीके से जुड़ी सामग्री किशोर मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। देश में संयुक्त परिवारों के बिखराव व बच्चों पर मां-बाप का नियंत्रण कम होने से कई किशोर बुरी संगति के चलते अपराधजगत की फिसलन में उतर जाते हैं। दूसरी ओर स्कूल-कालेजों में शिक्षकों की वह भूमिका नहीं रही, जो सख्ती से किशोरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। आज उनकी सोच को मोबाइल व सोशल मीडिया पर प्रसारित विकृत सूचनाएं प्रभावित कर रही हैं। समाज के व्यवहार में एक किस्म की आक्रामकता नजर आती है। वहीं दूसरी ओर आपराधिाक गिरोह व गैंग भी अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने कि लिए किशोरों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह भी है कि किशोरों तक घातक हथियार कहां से और कैसे पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, नशे की दलदल में फंसने वाले किशोर भी कालांतर नशा खरीदने के लिये पैसे जुटाने के लिये अपराध की गली में उतर जाते हैं। फिर गंभीर अपराधों को अंजाम देने लगते हैं। निश्चित रूप से बदलते वक्त के साथ पुलिस की भूमिका व कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही समाज में भी जागरूकता लानी आवश्यक है ताकि किशोरों को अपराध की राह पर बढ़ने से रोका जा सके। सरकार और समाज के साझे प्रयासों से ही इस संकट से उबरने में मदद मिल सकती है।

एन ई पी 2020 की प्रासंगिकता और शिक्षा का वर्तमान



राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी) 2020 को लागू हुए लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं। 2026 के वर्तमान परि. श्य में, यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज न रहकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उभर रही है। इसके संरचनात्मक बदलाव को देखिए। 5+3+3+4 मॉडल को समझिए। अब पारंपरिक 10+2 ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। 2026 तक अधिकांश राज्यों ने फाउंडेशनल स्टेज (3-8 वर्ष) पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। यह बच्चों के मस्तिष्क विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ता है, जिससे रटने के बजाय खेल-आधारित सीखने पर जोर बढ़ा है। एन ई पी 2020 की सबसे बड़ी ताकत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा (जैसे कोडिंग, बर्द्धग्रीरी, बागवानी) की शुरुआत है। इसकी वर्तमान स्थिति को देखिए। 2026 तक, भारत का लक्ष्य है कि कम से कम 50: शिक्षार्थियों को व्यावसायिक अनुभव मिले। यह डिग्री और रोजगार के बीच की खाई को पाटने में सबसे अधिक प्रासंगिक है। कोविड के बाद एन ई पी ने डिजिटल शिक्षा (दीक्षा स्वयं) को जो बढ़ावा दिया, वह अब स्थायी हो चुका है। वर्ष 2026 में, श्रेक्रेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी) पूरी तरह सक्रिय है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई के क्रेडिट्स डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार श्मल्टीपल एंट्री-एग्जिट (कभी भी पढ़ाई छोड़ने और वापस जुड़ने) का लाभ उठा सकते हैं। एन ई पी ने शिक्षकों को केवल प्छान देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक (मेंटर) बना दिया है। वर्ष 2030 तक 4-वर्षीय एकीकृत **B-Ed** डिग्री को अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।वर्तमान में, शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास (सी पी डी) और दीक्षा जैसे पोर्टल्स का उपयोग उनकी शिक्षण पद्धति को आधुनिक बना रहा है। वर्ष 2026 में एन ई पी 2020 की प्रासंगिकता इस बात में है कि यह भारत को प्लोबल नॉलेज सुपरपावर बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करती है। यह शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने का साधन न बनाकर सीखना कैसे है (लॉर्निंग हाउ टू वर्क) पर केंद्रित करती है।

लेखक विनय कांत मिश्र / दैनिक बुद्ध का संदेश

पानी आपूर्ति की निरंतरता व शुद्धता जरूरी

पिछले वित्त वर्ष में जल शक्ति मंत्रालय ने आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया, जो प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है। बजट 2026 में राज्यों के लिए 67,600 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग तभी सार्थक होगा जब उसे 'क्वालिटी अश्वडिट' से जोड़ा जाए। आज भी देश के 230 जिलों में आर्सेनिक और 469 जिलों में फ्लोराइड पानी में घुला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ...

भारत दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। यह असंतुलन ही देश में जल संकट की बुनियादी जड़ है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने नागरिकों को एक गिलास शुद्ध पानी देने में सक्षम हैं? इस साल के फरवरी 2026 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में जल शक्ति मंत्रालय के लिए 67,600 करोड़ रुपये का आवंटन कर सरकार ने अपनी मंशा तो साफ कर दी है। लेकिन जल जीवन मिशन और 'अमृत' जैसे प्रोजेक्ट्स के पिछले सात वर्षों के सफर को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्था ने केवल पाइप बिछाने की गति को ही सफलता मान लिया, जबकि पानी की शुद्धता और उसकी निरंतरता को हाशिए पर धकेल दिया गया। भारत के शहरी-ग्रामीण इलाकों में दूषित पानी को लेकर बात करें तो दिसंबर, 2025 से जनवरी 2026 के पहले सप्ताह के बीच ही देश के 26 प्रमुख शहरों में सीवेज मिश्रित पानी पीने से 5,500 से अधिक लोग बीमार हुए और कम से कम 34 लोगों की मौत दर्ज की गई। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दिसंबर, 2025 के अंतिम सप्ताह में पाइपलाइन

में सीवेज का पानी मिलने से 37 लोगों की मौत हो गई और 1,400 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच गए। इसी तरह, जनवरी, 2026 की शुरुआत में बेंगलुरु के पॉश इलाकों



और गांधीनगर (गुजरात) में सैकड़ों बच्चे दूषित पानी के कारण टाइफाइड और डायरिया का शिकार हुए। अगर, 2019 में जब 'जल जीवन मिशन' शुरू हुआ, तब लक्ष्य था 2024 तक हर घर को नल से जोड़ना। सरकारी पोर्टल के अनुसार, जनवरी 2026 तक देश के लगभग 15.8 करोड़ घरों में नल लग चुके हैं। लेकिन इस 'संख्यात्मक सफलता' के पीछे एक बड़ा ढांचागत दोष है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 79वें दौर के आंकड़ों के अनुसार, पाइपलाइन कवरेज के बावजूद केवल 39 प्रतिशत ग्रामीण घर ही नल के पानी को अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों

में यह उपयोग दर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच है। देखा गया कि हजारों गांवों में पाइप और नल तो लगे हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना कम है कि वह अंतिम घर तक नहीं पहुंचता। कई स्थानों पर तो नल केवल 'शोपीस' बनकर रह गए हैं। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के 60 प्रतिशत जल स्रोत सूख चुके हैं। मैदानी इलाकों में भूजल का स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है कि नलों के लिए पानी का कोई स्थायी स्रोत ही नहीं बचा है। जवाबदेही की कमी के कारण पाइपलाइनों बिछाने के कुछ महीनों बाद ही फटने लगी हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। कृषि में 'वाटर गजलर' फसलों (जैसे धान और गन्ना) के लिए अंधाधुंध पंपिंग ने जलभृतों (एक्वाफर्स) को सुखा दिया है। इन सभी कारणों से पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। बड़ी मात्रा में सतही जल प्रदूषित है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम की बढ़ती मात्रा 'कैंसर बेल्ट' जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है। गांवों से पलायन और शहरों का अनियोजित विकास, सरकार द्वारा तैयार मूलभूत संरचना पर आवश्यकता से अधिक बोझ ने महानगरों को पानी के लिए कंगाल बना दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइन लीकेज और सीवेज मिक्सिंग

एक आम समस्या बन गई है। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना 'अमृत 2.0' का लक्ष्य शहरों को 'वॉटर सिटीयर' बनाना था। लेकिन संसदीय स्थायी समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी भारत में अभी भी बड़ी मात्रा में पानी 'नॉन-रेवेन्यू वॉटर' के रूप में बर्बाद हो जाता है, जो मुख्य रूप से पाइपलाइनों के रिसाव के कारण होता है। सबसे बड़ी विफलता जल वितरण और सीवेज प्रबंधन के बीच समन्वय का अभाव है। बजट 2026 में सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया है। यह एक मूक स्वीकारोक्ति है कि 2024 और 2025 के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। बजट में इस बार 'वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग' और 'यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट' पर जोर दिया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल शहरी निकायों के पास नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में जल शक्ति मंत्रालय ने आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया, जो प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है। बजट 2026 में राज्यों के लिए 67,600 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग तभी सार्थक होगा जब उसे 'क्वालिटी ऑडिट' से जोड़ा जाए। आज भी देश के 230 जिलों में आर्सेनिक और 469 जिलों में फ्लोराइड पानी में घुला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े चेतावनी देते हैं कि असुरक्षित पानी से भारत में होने वाली मौतें तेजी से बढ़ सकती हैं।

जिन नेताओं से संपर्क किया गया, उनमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज और इटली की प्रधानमंत्री जिरोर्जिया मेलोनी शामिल थे। पाकिस्तान की लीडरशिप ने खाड़ी और मुस्लिम जगत के नेताओं से भी बात की, जिनमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, यूएई के राष्ट्रपति शेख ...

खाड़ी युद्ध टालने के लिए युद्धरत देशों को समझौता वार्ता की टेबल तक पहुंचाने का श्रेय पाक लेने की कोशिश में है। लेकिन हकीकत यह है कि इतनी जबरदस्त नेटवर्किंग अकेले पाक लीडरशिप के बस की नहीं थी। इस शांति प्रयासों में चीन, तुर्किये, अरब देशों तथा यूरोपीय नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान ने शांति समझौते का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, जिसमें तीनों पक्ष विजयी भाव से सीना ताने दुनिया के समक्ष खड़े हैं। बुधवार रात नेतन्याहू ने कहा, 'काम अभी अधूरा है, अभी और भी लक्ष्य पूरे करने हैं, हम उन्हें हासिल करेंगे'कृचाहे समझौते से, या फिर से लड़ाई शुरू करके। हमारी उंगली ट्रिगर पर है।' ईरान ने भी विजयी भाव से कहा कि हमारी ली उंगलियां ट्रिगर पर है, कभी भी दबा देंगे। दुनिया यही मान रही है कि 39 दिनों से चल रहा युद्ध खत्म हो गया। लेकिन, पिक्वर अभी बाकी है। शांति समझौते से अलग, एक और चौगुटा बैठक तुर्किये, सऊदी अरब, पाकिस्तान और मिन्न के विदेशमंत्री कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कैसे

वाशिंगटन और तेहरान का भरोसा जीता? पाक पावर कॉरिडोर के लोग बताते हैं, 'ईरान पर पहले हमले हुए, तो विदेश मंत्री इशाक डार, जो उप-ग्रह ानमंत्री भी हैं, सऊदी अरब में' थे, और 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' की एक बैठक में हिस्सा ले रहे थे। डार ने अराघवी को फोन करके अपनी एकजुटता जाहिर की।' इस्लामाबाद स्थित सनोबर इंस्टिट्यूट के एजीक्यूटिव डायरेक्टर कमर चीमा ने बताया, 'जब पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की, तो उसी पल उसने ईरानियों का भी दिल जीत लिया। पाकिस्तान ने जैसे स्वीकार किया, कि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद हमने भारत से युद्ध रोक लिया, ट्रंप हम पर फिदा हो गए।' सर्वोच्च नेता अली खामेनई की हत्या के बाद कराची में 1 मार्च



को प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। वहां की शिया मुस्लिम आबादी, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी का 15 से 20 प्रतिशत है, इस पूरे घटनाक्रम पर बापीकी से नजर रखे हुए थी। जैसे-जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को रावलपिंडी

बुलाया, और चेतावनी दी, कि पाकिस्तान के भीतर किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दीगर है कि शिया इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु प्रिंस रहीम अल-हुसैनी ने भारत-पाकिस्तान के शासन प्रमुखों को मेल किया था, कि वो चाहें तो तेहरान में सुलह का प्रयास कर सकते हैं। प्रिंस रहीम अल-हुसैनी के अलावा तीन और शिया धर्मगुरुओं को तेहरान से विश्वास बहाली के वास्ते एक्टिवेट किया गया। इनमें 'एक्टिवेट किया गया। इनमें शिया उलेमा काउंसिल के नेता सैयद साजिद अली नकवी, दूसरे शिया इमाम अल्लामा नजीर अब्बास तकवी, और 'तहरीक-ए-नफाज-ए-फिक्ह-ए-जाफरिया' के प्रमुख, हुसैन मुकद्दसी का नाम आया है। बहरहाल, होर्मुज जलडमरूमध्य य उन शर्तों के साथ फिर से खोलने की कोशिश है, जिनके तहत ईरान और ओमान ट्रॉजिट फीस वसूल सकेंगे। अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है, जिसमें लेबनान का सवाल भी है। ठीक से देखा जाये, तो इस पूरे शांति प्रयासों में पाकिस्तान प्यादा भर है, असल गोट तुर्किये के राष्ट्रपति रिजप तथ्यिप एर्दोआन, चीनी राष्ट्रपति शी, और यूरोपीय नेता खेल रहे थे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को युद्धविराम के प्रयासों में एक प्रमुख वार्ताकार के रूप में देखा जा रहा है, जो विशेष दूत स्टीव

विटकॉफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ औपचारिक बातचीत का नेतृत्व संभवतः उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, जिनके साथ ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे। कुशनर पहले भी ईरान के साथ बातचीत में शामिल रहे थे। 28 फरवरी को शुरू युद्ध में अमेरिका और इस्त्राइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए, जिनमें सुप्रीम लीडर अली खामेनई समेत कई शीर्ष नेतृत्व वाले मारे गए. ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस युद्ध से 3500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, दुनिया की तेल सप्लाई के लगभग पांचवें हिस्सा अवरुद्ध हो गया। इस बिन बुलाये युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। अंकारा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सहायक प्रोफेसर, बेतुल डोगन-अक्कास ने कहा कि पाकिस्तान के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण, वह मध्यस्थ की भूमिका के लिए एक स्वाभाविक पसंद बन गया। यह हफ्तों की

कड़ी कूटनीति का नतीजा हैय ऐसी कूटनीति जिसके बारे में बहुत कम लोगों को यकीन था, कि पाकिस्तान कर पाएगा। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की, कि 22 से 23 मार्च के बीच, मुनीर ने सीधे तौर पर ट्रंप से बात की थी। 29 मार्च को, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये और मिन्न के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में फिर से मिले। बैठक से पहले, शरीफ ने पेजेरिकयन के साथ लंबी बातचीत कीय पांच दिनों में यह उनकी दूसरी बातचीत थी। बातचीत के बाद, डार पेइचिंग गए, जो चीन की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, और दोनों पक्षों ने एक पांच-सूत्री रुपरेखा तैयार की, जिसमें

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा फ्रिटींग पब्लिकेशन हाउस... फ्रिटींग की खोज कीजिए और फ्रिटींग की खोज कीजिए

बुद्ध पब्लिकेशन

ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

● जी.एस.टी. प्रिंट बुक/फार्म ● कार्पोरल सैलैट ● स्कूल कार्ड/फार्म/अवरी ● फर्पलेट ● कलर पोस्टर ● कलर फ्लिपिड कार्ड ● सैलैट लेट पेड ● बैंक फार्म

लिकट-टीरो एजेंसी, बीनद मधुकरपुर-सिद्धार्थनगर (3.पु.)

☎ 8795951917, 9453824459

संपर्क: www.budhakasandesh.com

ईमेल: Dr. budhakasandesh@gmail.com

